

2/0/03

The Gazette of India

असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकावित PUBLISHED BY AUTHORITY

d• 636] **No.** 636] नई विश्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1984/पाँव 8, 1906

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1984/PAUSA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

. उद्योग मंत्रालय

(ब्रीद्यांगिक विकास विभाग)

आदेश

ं नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1984

का. आ. 973 (अ)/18कक/उ. वि वि.अ /84:—
केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूलपूर्व उद्याग और
नागरिक पूर्ति संवालय (आँद्योगिक विकास विभाग) के
आदेण सं. का.आ. 319 (अ) 18कक/उ वि वि.अ./76
तारीख 27 अप्रैल, 1976, द्वारा (जिस इसमें इसके पण्चात्
उक्त आदेण कहा गया है) मैं समं प्लाईवार्ड इंडस्ट्रीज लिसिटेड,
पाम्पार, जम्मू कण्मीर नामक सम्पूर्ण आद्योगिक उपक्रम
का प्रयन्ध 26 अप्रैल, 1981 तक की, जिसमें यह नारीख
भी समिलत है, पांच वर्ष की अविधि के लिए ग्रहण करने
के लिए जम्मू कण्मीर इंडस्ट्रीज लिसिटेड का प्राधिकृत किया
था,

श्राँग केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होते पर कि लांकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्विकत पाच वर्ष की अवधि की समाध्ति के पण्चात प्रमावी बना रहे 31 दिसम्बर 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्म-लित है, ग्राँग अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिये समय-भाग पर निर्देश जारों किये थे दिखए भारत सरकार के उद्योग मंतः लय (श्रौद्योगिक विकास विभाग) के आदेण सं. का.आ. 318(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./81, नारीख 25 अप्रैल, 1981, सं. का.आ. 287(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./82, 26 अप्रैल 1982, सं.का.आ. 763(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./82, नारीख 25 अवतूबर, 1982, सं.का.आ. 233 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83, नारीख 28 मार्च, 1983, सं.का.आ. 695 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83, नारीख 29 सितम्बर, 1983 सं.का.आ. 227 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./84, नारीख 30 मार्च 1984, का.आ. 473 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./84 नारीख 28 जून, 1984 स्थार का आ. 748 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./84 नारीख 28 जून, 1984 स्थार का आ. 748 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./84 नारीख 28 सितम्बर 1984

ग्रीर कन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह भमीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1985 तक की, जिसमें यह तारोख भी मस्मिलित है ग्रीर अवधिकें के लिए प्रभावी बना रहें,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास ग्रीर विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क को उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठिन धारा 186क का उपधारा 2 द्वारा प्रदन्त गक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त श्रादेश 31 मार्च, 1985 तक की, जिसमें यह नारीख भी साम्मिलित है, श्रीर श्रवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

> [फ . सं . 2(6)/81 सी०यू०एस] ए . पी० गरवन, संयुक्त मचिव

MINISTRY OF INDUSTRY (Department of Industrial Development) ORDER

New Delhi, the 29th December, 1984

S.O. 973(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (I partment of Industrial Development) No. S.O. 319(E)|18AA|IDRA|76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter deferred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu and Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs Plyboard Industries Limited, Pampere, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 26th April, 1981.

And, whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for soft continuance for a further period upto and included of the 31st December, 1984 [vide orders of the Givernment of India in the Ministry of Industry (Departmeent of Industrial Development) Nos. S.O. 318(E)[18AA]IDRA[81, dated the 25th April, 1981, S.O. 287(E)[18AA]IDRA[82, dated the 26th April, 1982, S.O. 763(E)[18AA]IDRA[82, dated the 25th October, 1982, S.O. 233(E)[18AA]IDRA[83, dated the 28th March, 1983, S.O. 695(E)[18AA]IDRA[83, dated the 29th September, 1983, S.O. 227(E)[18AA]IDRA[84, dated the 30th March, 1984, S.O. 473(E)[18AA]IDRA[84, dated the 28th June, 1984 and S.O. 748(E)[18AA]IDRA[84, dated the 28th September, 1984];

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Epvelopment and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985.

[File No. 2(6)|81-CUS] A. P. SARWAN, Jt. Secy.